**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) जी, हाँ दक्षेस वित्त मंत्रियों का सम्मेलन 10–11 जुलाई, 1994 को आयोजित हुआ।

(ख) सम्मेलन में निर्धनता विरोधी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। मंत्रियों ने क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाने की मूल आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में अपनाई गई प्रवृत्तियों की समीक्षा की और क्षेत्रीय सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीयवाद में वृद्धि की प्रवृत्ति पर सन्तुष्टि व्यक्त की। मंत्रियों ने आगे आभास किया कि दक्षेस के आंतरिक देशों के व्यापार को विस्तार दक्षेस देशों को एक साथ और अधिक समीप लाएगा और उनकी आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। उन्होंने बल दिया कि सुधार कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन पर त्वरित प्रयासों में सहायक होने चाहिए जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि अल्प काल में उनका निर्धन लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता। मंत्रियों ने यह सहमति व्यक्त की कि एक त्रीस्तरीय कार्यविधि स्थापित की जानी चाहिए जो निर्धनता को कम किए जाने की क्रियान्वयन में दक्षेस देशों के अनुभवों पर सूचना के विनिमय के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड**

**1968. श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड गठित करने का मामला किस चरण में है और इस तरह के गठन की पूरी प्रक्रिया क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 में दिए गए मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। इन कानूनों के अनुसार इन निदेशकों की नियुक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

**Tax benefits for handicapped people**

1969. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to extend more Income Tax exemption benefits for handicapped people;

(b) what are the details of the representation received by Government from associations representing handicapped people;

(c) what is the reaction of Government;

(d) whether it is a fact that handicapped people get income-tax benefits in other countries;

(e) whether Government would also extend Income Tax benefits to business units patronizing activities and sports of handicappel people; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Government receives representation from time to time from various associations representing handicapped people for extending the scope of the tax concessions available to handicapped persons. Responding to these suggestions, the scope of several tax concessions have been enlarged.